तकनीकी मिशनों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा

1110. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच टैक्नीकल मिशनों (प्रौद्योगिकी मिशन) के लिये "सामाजिक लेखा परीक्षा" का प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार के मूल्यांकन के अनुसार उपर्युक्त मिशन अपने मुख्य उद्देश्यों में कहां तक सफल रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी अभिकरणों द्वारा किये जा रहे दावों का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करना, और

विश्वसनीय और प्रयोजनमूलक पुनर्निवेश की प्रणाली स्थापित करना जो लोगों की आवश्यकताओं, चिन्ताओं और समस्याओं के प्रति जागरूक होगी ।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिये राष्ट्रीय मिशन प्रलेखों में उल्लिखित उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

बड़े बांधों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

1111. **श्री अजीत जोगी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े बांधों के निर्माण पर उस समय तक प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है, जब तक कि सिंचाई विभाग द्वारा बड़े-बड़े बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले आवासी लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म, आर्थिक और शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से पुनर्वासित नहीं कर दिया जाता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्णय को नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजना पर भी लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले इन जन-जातीय लोगों के उचित पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से नये और प्रभावी वैकल्पिक कदम उठाये जायेंगे ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । स्वीकृति तथा योजनाओं में शामिल करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं की जांच करते समय, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण आवश्यक पुनर्वास तथा पुनःस्थापन कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं

(ख) और (ग) जहां तक नर्मदा सागर तथा सरकार सरोवर परियोजनाओं का संबंध है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के लिये राज्य के प्रस्ताव का निरीक्षण करने तथा इस मामले में आवश्यक निदेश देने के लिये भारत सरकार के सचिव (कल्याण) की अध्यक्षता में पुनर्वास संबंधी विशिष्ट उप-समूह है

मृत/विकलांग अधिकारियों के आश्रितों का पुनर्वास

1112. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध में मारे गये अथवा ऐसे युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग